(a) whether it is a fact that a large number of workers from the Paradeep Phosphates Limited, Orissa have been retrenched;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether wages are not being paid to the workers regularly; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Wages are being paid to the workers regularly.

Irregularities at Mother Dairy Booths in Delhi

841. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the quality of fruits and vegetables supplied at Mother Dairy booths in Delhi is poor and prices higher as compared to those in the open market;

(b) the mechanism evolved to ensure that there is no connivance between the purchasing, marketing and vigilance departments; and

(c) whether it is a fact that two specific complaints in this regard were made in October 1996 at Booth No. 605 in *'C* block of Janak Puri, if so, whether the said complaints have been brought to the notice of higher authorities and necessary action taken to remove the grievance, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) Neither the quality of fruits and vegetables supplied at Mother Dairy fruit and vegetable booths in Delhi is poor nor their prices are higher as compared to prices in shops in the markets.

(b) Quality and pricing of produce procured/ sold are regularly monitored.

(c) Yes Sir, both the complaints were attended, to remove the grievances.

Community forest management in protected areas

842. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI-RAO SHINDE:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the concept of Community Forest Management in Protected Areas mooted by a Dehradun based NGO has evoked the interest of World Bank;

(b) if so, the details of this concept; and

(c) the steps being taken to popularise it and put it into practice for promoting Community Forest Management in different parts of the country with or without the aid of World Bank?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) On the advice of the World Bank, the Rural Litigation and Entitlement Kendra (RLEK), Dehra Dun has sent the report prepared by them on the subject to this Ministry for consideration.

(b) and (c) The concept largely combines the approaches being followed under the Joint Forest Management (JFM) and Ecodevelop-ment initiatives which are already under implementation in various forest areas and wildlife protected areas respectively. However, the implementation of the suggested strategy in protected areas can only be done within the framework of the legal provisions under the Wildlife (Protection) Act, 1972.

नयी रेल लाइन के संबंध में निर्धारित मानदण्ड

843. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नयी रेल लाइनों के निर्माणार्थ सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) इस वर्ष के दौरान, सरकार ने किन-किन राज्यों में नयी रेल लाइनों के निर्माण संबंधी कार्य शुरु किये हैं,

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इस वर्ष के दौरान, अथवा चालू योजनावधि के अन्त तक कुछ राज्यों में नयी रेल लाइनों का निर्माण किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू बजट में तथा चालू योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा गुजरात में कौन-कौन सी परियोजनायें शुरु की गई है तथा उन पर कितनी लागत आयेगी?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) रेलों पर नई लाइनों में निर्माण के लिए अपनाए जा रहे प्राचल राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति, मई, 1990 की सिफारिशों पर आधारित हैं जिसने नई लाइनों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए थे;

1. खनिज और अन्य संपदाओं के दोहन के लिए नए उद्योगों को सेवित करने वाली परियोजना उन्मुख लाइनें;
2. मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए पूर्ण वैकल्पिक मार्गों के लिए अप्राप्त कड़ियां;
3. सामरिक महत्व के लिए अपेक्षित लाइनें; और
4. नए विकास केन्द्रों की स्थापना या दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन के लिए लाइनें।

नई लाइनें परियोजनाएं उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर शुरु की गई हैं प्रत्येक मामले में प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जाता है, और तत्पश्चात् सर्वेक्षण के परिणामों से परियोजना की अर्थक्षमता सिद्ध हो जाने या परियोजनाएं उपरोक्त एक मानदण्ड के अनुरूप होने पर, रिपोर्ट योजना आयोग को उनके विचारार्थ भेज दी जाती है और उनका अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर 50 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तारित बोर्ड और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और तत्पश्चात् रेल बजट के माध्यम से कार्य शुरु किया जाता है। 50 करोड़ रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए कार्यों को रेल बजट में शामिल करने से पहले केवल योजना आयोग का ही अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाएं शुरु की गई हैं/शुरु की जाएंगी:-

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	राज्य	96-97 में आबंटित धन-राशि (करोड़ रु॰ में)
1.	नंदयाल-येरागुंटला	आंध्र प्रदेश	0.50
2.	सकरी-हसनपुर	बिहार	3.00
3.	कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	कर्नाटक	1.00
4.	हरिदासपुर-पारादीप	उड़ीसा	1.00
5.	दौसा-गंगापुर सिटी	राजस्थान	0.50
6.	कुमारघाट-अगरतला	त्रिपुरा	1.00

(घ) जी हां।

(ङ) इस वित्त वर्ष में निम्नलिखित लाइनें पूरी कर ली गई हैं/पूरी कर ली जाएंगी:-

1. ब्यास - गोइंदवाल (27 कि.मी.) पंजाब में।
2. छितौनी - बगहा (19 कि.मी.) उ. प्र. और बिहार में।
3. करन्जलि - निश्चिंतपुर (8 कि.मी.), पश्चिम बंगाल में।

(च) चालू योजना अवधि के दौरान गुजरात में कोई नई लाइन परियोजना शुरु नहीं की गई है।

Feasibility of Compact University

844. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have examined the concept of "Compact University";

(b) whether it is a fact that an exercise on the feasibility of "Compact Universities" is necessary;

(c) whether any representation has been received in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) There are certain representation in this regard. However, the Govt, of India does